सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2017-2018

श्रीमती वसुन्धरा राजे

मुख्यमंत्री
का बजट भाषण

8 मार्च, 2017

फाल्गुन शुक्ल ११, विक्रम संवत् २०७३

बजट 2017 - 2018

डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन

आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी :

273. राज्य में महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ, आमजन को विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पारदर्शी रूप से प्रदान करने के लिए हमनें 15 अगस्त 2014 से भामाशाह योजना को पुनः major रूप से लागू किया है। प्रारंभिक क्रियान्वयन में आयी कठिनाइयों का समाधान करते हुए भामाशाह platform के माध्यम से **सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति, राजश्री योजना, जननी**

http://finance.rajasthan.gov.in

सुरक्षा योजना, पालनहार योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना तथा राशन वितरण आदि को जोड़ा जा चुका है। साथ ही, चरणबद्ध रूप से अन्य योजनाओं को भी भामाशाह योजना से जोड़ा जा रहा है।

274. प्रदेश में banking and digital payment की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राजस्थान payment platform का निर्माण कर समस्त e-payment gateway, credit card, debit card, Ru-Pay card एवं mobile wallet को भी जोड़ा गया है। साथ ही, bio-metric आधारित भुगतान की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 23 हजार 500 से अधिक ई–मित्र micro ATM स्थापित किये गये हैं, **जोकि देश में सर्वाधिक हैं।**

275. प्रदेशवासियों को e-Governance और good governance देने की दिशा में ई–मित्र एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। राज्य में ई–मित्र service delivery केन्द्र ग्राम पंचायत स्तर तक सभी अटल सेवा केन्द्रों पर भी उपलब्ध हैं। अब इस सुविधा को और बेहतर बनाते हुए सभी अटल सेवा केन्द्रों पर ई–मित्र service ATM स्थापित किये जायेंगे। जहाँ कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा, सूचना तथा आवश्यकता के अनुसार दस्तावेजों के प्रिंट ले सकेगा।

276. सरकारी कार्यालयों की क्षमता बढ़ाने, कार्यों में पारदर्शिता के साथ गति प्रदान करने हेतु राज e-office के तहत leave sanction, APAR, inventory, and meeting management जैसी सुविधायें 5 विभागों में प्रारंभ की गई हैं। दस प्रमुख विभागों में शीघ्र ही यह सुविधा

लागू कर दी जायेगी। आगामी वर्ष में सभी प्रमुख विभागों में file tracking system भी लागू किया जायेगा।

277. विभिन्न online सुविधायें देने हेतु जिला मुख्यालयों के कार्यालयों को fibre के माध्यम से connect कर दिया गया है। आगामी वर्ष में सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं नगर निकाय मुख्यालय को fibre से connect किया जायेगा।

278. अटल सेवा केन्द्रों पर युवाओं को internet की सुविधा देने के लिए चरणबद्ध रूप से wi-fi सुविधा प्रारंभ की जायेगी। इसके अलावा समस्त राजकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ITI, पोलिटेक्निक तथा राजकीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से wi-fi की सुविधा **निःशुल्क** उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

279. गत् वर्ष हमनें 2 लाख प्रदेशवासियों को IT training देने की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमनें लगभग 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है। आगामी वर्ष में **8 लाख लोगों** को IT training दी जायेगी।

280. गत् वर्ष हमनें नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर IT enabled एकीकृत Command and Control Centres स्थापित करने की घोषणा की थी। संभागीय मुख्यालयों पर लगाये गये इस infrastructure का समुचित उपयोग करते हुए आगामी वर्ष सभी जिलों को भी Command and

http://finance.rajasthan.gov.in

Control Centres से जोड़ते हुए जिला मुख्यालयों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की CCTV कैमरों से निगरानी, समस्त आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों का संचालन एवं नागरिक हैल्पलाईन सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

281. हमारा प्रयास है कि आमजन को चिकित्सा सेवाओं को लाभ बेहतरीन तरीके से और आसानी से अपने नजदीकी अस्पताल एवं डिस्पेंसरी में ही प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं राज्यव्यापी integrated IT enabled health project की घोषणा करती हूँ। इसके माध्यम से telemedicine की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जायेगी।

282. खनन से संबंधित समस्त कार्यों को दक्षतापूर्वक एवं पारदर्शी रूप से संपादित करने के लिए आगामी वर्ष integrated online system को develop किया जायेगा, जिसमें लीज देने, रवन्ना जारी करने से लेकर अवैध माईनिंग तक के सभी कार्य IT एवं GIS के माध्यम से किये जायेगें।

283. डिजिटल राजस्थान का सपना साकार होने के साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य में cyber security पर समुचित ध्यान दिया जाये। हमनें IT security policy का IT एवं ITES policy में समावेश करते हुए राज्य के data centre एवं नेटवर्क को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया है। इस वर्ष जयपुर में cyber forensic cell प्रारंभ कर दी गई है। आगामी वर्ष शेष 6 संभागीय मुख्यालयों पर cyber forensic cell प्रारंभ किये जायेंगे।